

DOI: 10.53555/ks.v13i2.3909

Unveiling Potential: A Strategic Roadmap for Domestic and International Market Development for Indian MSMEs

Mr. Satish Kumar^{1*},

^{1*}Research Scholar, Jayoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur

Supervisor Dr. Suman²,

²Jayoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur

Abstract

Small and Medium Enterprises (MSMEs) are the backbone of emerging and developed economies. Small and Medium Enterprises (MSMEs) contribute significantly to the gross domestic product, employment, and innovation in the Indian economy. However, despite their importance, Indian MSMEs face several challenges, including limited access to capital, outdated technology, poor infrastructure, and weak market competitiveness. This research paper examines how policy reforms, digital transformation, financial inclusion, skill development, and international partnerships can enhance MSME opportunities in domestic and international markets. This analysis is based on a review of recent initiatives under the Make in India campaign and statistical data. It proposes a multi-dimensional strategy to empower MSMEs as engines of inclusive and sustainable development. This study identifies the key factors that enhance MSME competitiveness. It also addresses regulatory barriers, infrastructure deficits, and limited market access as major challenges.

Keywords: MSMEs, India, domestic market, international trade, digitalization, policy reforms, competitiveness.

संभावनाओं को उजागर करना: भारतीय एमएसएमई के लिए घरेलू और वैश्विक विकास हेतु एक रणनीतिक रोडमैप।

Mr. Satish Kumar, Research Scholar, Jayoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur

Supervisor Dr. Suman, Jayoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur

सारांश

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) उभरती और विकसित दोनों अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक विकास की रीढ़ हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद, रोजगार और निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, हालाँकि, अपने महत्व के बावजूद, भारतीय एमएसएमई कई चुनौतियों का सामना करते हैं, जिनमें पूंजी तक सीमित पहुँच, अपर्याप्त तकनीक, खराब बुनियादी ढाँचा और कमज़ोर वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता शामिल है। यह शोध पत्र इस बात की जाँच करता है कि नीतिगत सुधारों, डिजिटल परिवर्तन, वित्तीय समावेशन, क्षमता निर्माण और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के माध्यम से घरेलू और वैश्विक दोनों बाजारों में एमएसएमई के अवसरों को कैसे बढ़ाया जा सकता है। यह अध्ययनसाहित्य की समीक्षा, द्वितीयक आंकड़ों के विश्लेषण और आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियानों के तहत हाल की पहलों पर आधारित है। यह एमएसएमई को समावेशी और सतत विकास के इंजन के रूप में सशक्त बनाने के लिए एक बहुआयामी रणनीति का प्रस्ताव करता है। यह अध्ययन एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने वाले सक्षम कारकों का विश्लेषण करता है। यह नियामक बाधाओं, बुनियादी ढाँचे की कमी और सीमित वैश्विक पहुँच सहित प्रमुख चुनौतियों का भी समाधान करता है।

कीवर्ड: एमएसएमई, भारत, घरेलू बाजार, वैश्विक व्यापार, डिजिटलीकरण, नीति

सुधार, प्रतिस्पर्धात्मकता।

परिचय

MSME का अर्थ है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम। ये ऐसे व्यवसाय हैं जिन्हें संयंत्र और मशीनरी या उपकरणों में उनके निवेश और

उनके वार्षिक कारोबार के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। भारत में, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय इस क्षेत्र का प्रबंधन और समर्थन करता है, जो आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और नवाचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) 21वीं सदी में आर्थिक परिवर्तन के गतिशील और लचीले चालक के रूप में उभरे हैं। अपने महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद, MSMEs अनौपचारिकता, अपर्याप्त वित्त पोषण, पुरानी तकनीक और बाजार पहुँच की कमी जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। वैश्वीकरण, डिजिटल व्यापार और क्षेत्रीय एकीकरण के नए अवसर पैदा कर रहे हैं, और उनकी पूरी क्षमता का दोहन करने के लिए, भारत को घरेलू और वैश्विक दोनों बाजारों में MSMEs के लिए अवसरों को बढ़ाने के लिए एक बहुआयामी रणनीति अपनानी चाहिए। भारतीय MSMEs को स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विस्तार और प्रतिस्पर्धा करने के लिए उपयुक्त रणनीतियों के साथ समर्थन दिया जाना चाहिए।

अध्ययन के उद्देश्य

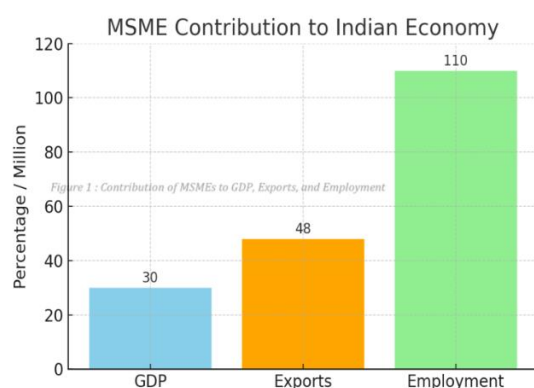
- भारतीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) के सामने मौजूदा चुनौतियों का विश्लेषण करना।
- घरेलू और वैश्विक क्षेत्रों में उनकी बाजार पहुँच बढ़ाने के लिए प्रमुख रणनीतियों की पहचान करना।
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) को समर्थन देने के उद्देश्य से सरकारी योजनाओं और पहलों का पता लगाना।
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार के लिए कार्रवाई योग्य कदमों की सिफारिश करना।

कार्यप्रणाली

- यह शोध द्वितीयक डेटा विश्लेषण पर आधारित है, जिसमें सरकारी रिपोर्टें
- (MSME मंत्रालय, RBI), शोध पत्र, उद्योग प्रकाशन (FICCI, CII), और नीति शामिल हैं।

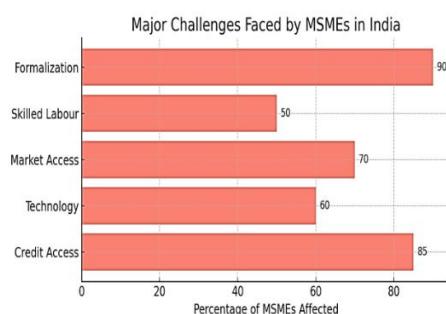
दस्तावेज़। बाज़ार की गतिशीलता और विकास के अवसरों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए डेटा एकत्र और व्याख्या किया गया है। भारतीय एमएसएमई का वर्तमान परिदृश्यपरंपरागत रूप से एमएसएमई को औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र में सहायक खिलाड़ियों के रूप में देखा जाता था। हालाँकि, समय के साथ बढ़ते हुए उन्होंने अब अर्थव्यवस्था के रणनीतिक विकास निर्माताओं के रूप में एक स्थिति का प्रशंसा प्राप्त कर ली है। भारत में वे

चित्र 1: सकल घरेलू उत्पाद, निर्यात और रोजगार में एमएसएमई का योगदान जीडीपी का लगभग 30%, निर्यात का 48% हिस्सा हैं, और 11 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं (एमओएमएसएमई, 2023)। स्थानीय स्तर पर, एमएसएमई को नीतिगत समर्थन, डिजिटलीकरण, क्षेत्रीय बाजारों तक पहुँच और आपूर्ति श्रृंखलाओं में एकीकरण से लाभ होता है। वैश्विक स्तर पर, बढ़ते व्यापार उदारीकरण, ई-कॉमर्स विस्तार और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं ने एमएसएमई के लिए नए रास्ते खोले हैं। एमएसएमई स्थानीय और वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और नवाचार, रोजगार सृजन और समावेशी विकास के इंजन के रूप में अपनी क्षमता के लिए जाने जाते हैं। वर्तमान में, भारत सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को समर्थन देने के लिए कई पहल कर रही है, जिनमें वित्तीय सहायता, कौशल विकास, प्रौद्योगिकी उन्नयन और बाज़ार पहुँच पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रमुख कार्यक्रमों में पीएमईजीपी, सीजीटीएमएसई और पीएम विश्वकर्मा जैसे कार्यक्रम शामिल हैं, जिनका उद्देश्य उद्यमिता को बढ़ावा देना, रोजगार बढ़ाना और अनौपचारिक क्षेत्र को एकीकृत करना है। वित्तीय सहायता प्रदान करने और ऋण तक पहुँच को आसान बनाने के लिए, सरकार ने कई योजनाएँ शुरू की हैं, जैसे - सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट।



(CGTMSE) नए और मौजूदा MSME को ₹2 करोड़ तक का बिना किसी जमानत के ऋण प्रदान करता है। सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (CGTMSE) बिना किसी जमानत और तृतीय-पक्ष गारंटी के 5 करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी प्रदान करता है, जो पहली पीढ़ी के उद्यमियों को स्टार्टअप की योजना बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। मुद्रा योजना (सूक्ष्म इकाई विकास एवं पुनर्वित्त एजेंसी) तीन श्रेणियों के तहत ऋण प्रदान करती है: शिशु (₹50,000 तक), किशोर (₹50,000 से ₹5 लाख तक), और तरुण (₹5 से ₹10 लाख तक) ताकि व्यक्तियों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार निवेश चुनने में मदद मिल सके। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) गैर-कृषि क्षेत्रों में नए उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने और उन्हें ऋण-संबंधी सब्सिडी प्रदान करने का काम करता है। अधीनस्थ ऋण के लिए ऋण गारंटी योजना (CGSSD) MSMEs के लिए ऋण गारंटी प्रदान करती है। आत्मनिर्भर भारत (SRI) कोष योग्य MSMEs को इक्विटी निवेश के माध्यम से विकास पूंजी प्रदान करता है। उद्योगिनी योजना, महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। MSMEs को वृद्धिशील ऋण के लिए ब्याज अनुदान योजना, GST-पंजीकृत MSMEs के लिए ₹1 करोड़ तक के ऋण पर 2% ब्याज अनुदान प्रदान करती है। इसके अलावा, सरकार आपातकालीन स्थितियों के कारण होने वाली बाधाओं से उबरने में लोगों की मदद के लिए आपातकालीन योजनाएँ भी शुरू करती है, जैसे- आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS), जो कार्यशील पूंजी प्रदान करने और तरलता चुनौतियों का सामना करने के लिए COVID-19 के दौरान शुरू की गई थी। श्रमिकों के प्रदर्शन को उन्नत करने के लिए कौशल विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम (ESDP) जैसे ये कार्यक्रम श्रमिकों को बदलते रुझानों के साथ तालमेल बिठाने में सक्षम बनाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। सरकार ने प्रौद्योगिकी केंद्र (टूल रूम) भी स्थापित किए हैं जो उपकरण निर्माण, उत्पाद डिज़ाइन और गुणवत्ता नियंत्रण में विशेष प्रशिक्षण और सेवाएँ प्रदान करते हैं। सार्वजनिक खरीद के अंतर्गत खरीद नीति

एमएसएमई नीति आदेश, 2012, केंद्रीय मंत्रालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अपनी ज़रूरतों का कम से कम 25% एमएसएमई से खरीदने का आदेश देता है, जिससे उन्हें अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए आउटलेट उपलब्ध होते हैं। व्यापार संबंधी उद्यमिता सहायता और विकास (TREAD) योजना इन उद्यमियों को अनुदान और क्षमता निर्माण सहायता प्रदान करके महिला उद्यमिता को बढ़ावा देती है। एमएसएमई चैंपियंस पोर्टल एमएसएमई के लिए शिकायत निवारण, सहायता और सहायता के लिए वन-स्टॉप प्लेटफ़ॉर्म प्रदान करता है। ZED प्रमाणन (शून्य दोष शून्य प्रभाव) एमएसएमई को न्यूनतम पर्यावरणीय प्रभाव वाले गुणवत्तापूर्ण उत्पादों का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजनाएँ एमएसएमई को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेने में सहायता करती हैं। डिजिटल और डिजिटल एमएसएमई योजना के माध्यम से तकनीकी सहायता एमएसएमई के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल उपकरणों को बढ़ावा देती है। रैंप योजना (एमएसएमई के प्रदर्शन को बढ़ाना और तेज करना) एमएसएमई की उत्पादकता और वित्तपोषण में सुधार के लिए विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त एक पहल है। सरकारी लाभ प्राप्त करने के लिए पैन और आधार से जुड़ी उद्यम पंजीकरण प्रणाली को अनिवार्य कर दिया गया है। पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए निधि योजना (स्फूर्ति) क्लस्टर-आधारित विकास और बुनियादी ढाँचे के माध्यम से खादी और कॉयर जैसे पारंपरिक उद्योगों का समर्थन करती है। सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) क्लस्टर निर्माण के माध्यम से एमएसएमई की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। एमएसएमई द्वारा हमारी अर्थव्यवस्था को प्रदान किए गए व्यापक समर्थन के बावजूद, उन्हें अभी भी कई बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें नियामक घाटे और सीमित वैश्विक पहुँच शामिल हैं। परिणामस्वरूप, उनमें से अधिकांश अभी भी अनौपचारिक हैं।



और उनमें से केवल 15% के पास संस्थागत ऋण तक पहुँच है। कुछ प्रमुख मुद्दों में कम डिजिटल अपनाना, पुरानी तकनीक और खराब बाजार पहुँच शामिल हैं। वित्त संबंधी पर्याप्त ज्ञान का अभाव, डिजिटल साक्षरता का अभाव जिसके कारण कई एमएसएमई ऑफ़लाइन काम करते हैं और उन डिजिटल उपकरणों से अनभिज्ञ हैं जो उनके काम की दृश्यता और दक्षता को बढ़ा सकते हैं। एमएसएमई के पास अक्सर प्रतिस्पर्धी बाजारों में खुद को बढ़ावा देने के लिए नेटवर्क और संसाधनों की कमी होती है। इससे परिचालन लागत में उल्लेखनीय वृद्धि होती है और उत्पादकता प्रभावित होती है। खराब समन्वय, वास्तविक समय के आंकड़ों की कमी और अविश्वसनीय लॉजिस्टिक्स के कारण स्टॉक खत्म हो जाता है या अतिरिक्त इन्वेंट्री हो जाती है, जिससे ग्राहक संतुष्टि बाधित होती है। ये अक्षमताएँ एमएसएमई की प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता को सीमित करती हैं, बाजार पहुँच को प्रतिबंधित करती हैं और समय पर डिलीवरी में बाधा डालती हैं, जिससे अंततः लाभप्रदता और विकास क्षमता प्रभावित होती है। अधिकांश एमएसएमई में अनुसंधान और उत्पाद नवाचार की क्षमता का अभाव होता है। कौशल की कमी के कारण गलत जगह पर स्थित नवाचार केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र और औसत दर्जे की ब्रांडिंग उत्पादकता, प्रतिस्पर्धा और नवाचार को प्रभावित करके एमएसएमई के विकास में महत्वपूर्ण रूप से बाधा डालती है। इससे उत्पादन में कमी, दोषों में वृद्धि, नई तकनीकों को अपनाने में कठिनाई और गुणवत्ता मानकों को पूरा करने में चुनौतियाँ आ सकती हैं। खराब बुनियादी ढाँचा देरी, लागत में वृद्धि और बाजार पहुँच को सीमित करके विकास में बाधा डालता है। अपर्याप्त परिवहन, अविश्वसनीय बिजली, और पुरानी रसद व्यवस्था उत्पादन और वितरण को बाधित करती है। ये चुनौतियाँ दक्षता को कम करती हैं, प्रतिस्पर्धात्मकता को कमजोर करती हैं और एमएसएमई को परिचालन बढ़ाने या व्यापक घरेलू और वैश्विक बाजारों में प्रवेश करने और उन्हें तलाशने से रोकती हैं। अपर्याप्त जागरूकता, खराब बुनियादी ढाँचे, जटिल निर्यात प्रक्रियाओं, प्रमाणन की कमी और सीमित वित्तीय सहायता, भाषा संबंधी बाधाओं, अपर्याप्त डिजिटल उपस्थिति और कम उत्पाद नवाचार के कारण सीमित वैश्विक बाजार पहुँच उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता को और कम करती है, जिससे एमएसएमई के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करना और वैश्विक व्यावसायिक नेटवर्क स्थापित करना मुश्किल हो जाता है।

बाज़ार के अवसरों को बढ़ाने की रणनीतियाँ:

आर्थिक परिदृश्य पर स्थायी परिवर्तनकारी प्रभाव डालने के लिए, जमीनी स्तर पर प्रयास किए जाने आवश्यक हैं। निष्कर्ष बताते हैं कि रणनीतिक समर्थन और सुधारों के साथ, एमएसएमई सतत आर्थिक विकास और वैश्विक व्यापार एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। यह पत्र एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूत करने और स्थानीय क्षमताओं और वैश्विक अवसरों के बीच की खाई को पाटने के लिए सुझाव प्रस्तुत करता है।

वित्त तक पहुँच को आसान बनाना:

वित्त एमएसएमई के लिए प्राथमिक बाधाओं में से एक बना हुआ है। वित्तीय सहायता सभी व्यावसायिक गतिविधियों का आधार बनती है, इसलिए एमएसएमई के लिए वित्त तक पहुँच को आसान बनाना सर्वोच्च प्राथमिकता बन जाती है। इस प्रक्रिया में ऋण प्रक्रियाओं को सरल बनाना, संपार्श्विक-मुक्त ऋण प्रदान करना, डिजिटल ऋण प्लेटफार्मों को बढ़ावा देना और सरकारी ऋण योजनाओं का विस्तार करना शामिल है। यह व्यवसायों को समय पर धन सुनिश्चित करके, अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भरता कम करके और विभिन्न क्षेत्रों और क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ाकर, वैश्विक स्तर पर बढ़ने, नवाचार करने और प्रतिस्पर्धा करने में मदद करता है। सरकार बैंकों को बिना किसी संपार्श्विक के ऋण देने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु - ऋण गारंटी योजना का विस्तार, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट (CGTMSE) जैसी योजनाओं को शुरू और सुदृढ़ कर सकती है। वित्तीय अंतराल को पाटने के लिए, विशेष रूप से MSMEs को लक्षित करते हुए, फिन-टेक समाधानों, पीयर-टू-पीयर उधार, और उद्यम पूंजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए वैकल्पिक वित्तपोषण मॉडल अपनाए जा सकते हैं। कार्यशील पूंजी की चुनौतियों को कम करने के लिए TReDS (व्यापार प्राप्त्य छूट प्रणाली) जैसे प्लेटफार्मों को लोकप्रिय बनाया जाना चाहिए।

डिजिटल परिवर्तन का लाभ उठाना

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के व्यापार बाजारों के रूप में उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पहल की आवश्यकता है। डिजिटल परिवर्तन का लाभ उठाने से क्लाउड कंप्यूटिंग के माध्यम से एमएसएमई सशक्त होते हैं, और डिजिटल भुगतान लागत कम करके, संचालन को सुव्यवस्थित करके और नवाचार को बढ़ावा देकर दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करते हैं, जिससे बाजार में उनका दायरा बढ़ता है और ग्राहक जुड़ाव में सुधार होता है। सरकारी और औद्योगिक इकाइयों को डिजिटल मार्केटिंग, ई-कॉमर्स और ऑनलाइन भुगतान में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम चलाने चाहिए। ओएनडीसी (डिजिटल कॉमर्स के लिए खुला नेटवर्क) जैसी पहल एमएसएमई को बड़े ई-कॉमर्स खिलाड़ियों पर निर्भर हुए बिना व्यापक बाजारों तक पहुँचने में मदद कर सकती है। क्लाउड-आधारित उद्यम संसाधन नियोजन प्रणालियों तक सब्सिडी वाली पहुँच उत्पादकता और निर्णय लेने की क्षमता में सुधार कर सकती है। यह बदलाव एमएसएमई को डेटा-संचालित निर्णय लेने, बेहतर ग्राहक जुड़ाव और वैश्विक बाजारों तक पहुँच, लगातार बदलते रुझानों के साथ त्वरित अनुकूलन, नवाचार को बढ़ावा देने, लचीलापन और तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था में सतत विकास के माध्यम से वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाता है।

आपूर्ति श्रृंखलाओं को मज़बूत करना

एमएसएमई के लिए स्थानीय आपूर्ति श्रृंखलाओं को मज़बूत करने में क्षेत्रीय सोर्सिंग को बढ़ावा देना, लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढाँचे में सुधार करना और स्थानीय उत्पादकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना शामिल है। क्लस्टर विकास को प्रोत्साहित करना, आपूर्ति नेटवर्क का डिजिटलीकरण करना और लचीलापन सुनिश्चित करने, आयात पर निर्भरता कम करने और दक्षता बढ़ाने के लिए नीतिगत समर्थन प्रदान करना। प्रभावी बाज़ार संपर्कों के माध्यम से क्लस्टर विकास और स्थानीय सोर्सिंग पहल, अंतिम छोर तक संपर्क स्थापित करने में मदद कर सकती हैं। व्यापार मेलों, एक्सपो और क्रेता-विक्रेता बैठकों जैसे B2B नेटवर्किंग कार्यक्रमों के माध्यम से प्रचार क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर अधिक बार आयोजित किया जाना चाहिए। ये प्रयास स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देने और एमएसएमई को स्थायी रूप से फलने-फूलने के लिए सशक्त बनाने में मदद कर सकते हैं। निर्यात संवर्धन परिषदों और वाणिज्य मंडलों का सक्रिय समर्थन मदद कर सकता है।

एमएसएमई नए वैश्विक बाज़ारों की पहचान करते हैं और उनमें प्रवेश करते हैं। विशिष्ट क्षेत्रीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग का प्रावधान वैश्विक मान्यता और माँग को बढ़ा सकता है। लगातार अनुसंधान के माध्यम से कौशल विकास और नवाचार।

एमएसएमई के माध्यम से विकास और नवाचार के लिए कौशल बढ़ाने में लक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रम,

उद्योग-अकादमिक साझेदारी, और आधुनिक तकनीकों तक पहुँच शामिल है। अनुसंधान और विकास निरंतर सीखने की संस्कृति को बढ़ावा देने और इनक्यूबेटरों का समर्थन करने में मदद कर सकता है, जबकि नवाचार केंद्र एमएसएमई को क्षमताओं को उन्नत करने, उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार करने और गतिशील घरेलू और वैश्विक बाज़ारों में प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए सशक्त बना सकते हैं। सहयोगात्मक अनुसंधान एवं विकास के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी एमएसएमई को नई तकनीकों को अपनाने और सह-विकास करने में सक्षम बना सकती है। एमएसएमई नवाचार योजना के तहत नवाचार अनुदानों तक पहुँच का पुनर्गठन किया जाना चाहिए ताकि एमएसएमई नवाचार केंद्रों की स्थापना और उत्पादों को ब्रांड के रूप में बढ़ावा देने में सहायता मिल सके जिससे घरेलू और वैश्विक बाज़ारों तक उनकी पहुँच बढ़ सके। स्टार्टअप और नवाचार केंद्रों को बढ़ावा देने के लिए इनक्यूबेशन केंद्रों और टेक पार्कों को विश्वविद्यालयों और निजी संस्थानों के साथ जोड़ा जाना चाहिए।

बुनियादी ढाँचा और रसद

बुनियादी ढाँचे और रसद को मज़बूत करने से उन अक्षमताओं को दूर करने में मदद मिल सकती है जो एमएसएमई के विकास और प्रतिस्पर्धात्मकता में बाधा डालती हैं। बेहतर सड़कों, बिजली आपूर्ति, इंटरनेट कनेक्टिविटी और औद्योगिक समूहों में निवेश करके सुचारू संचालन और रसद को बढ़ावा देने से यात्रा की लागत कम हो सकती है। एमएसएमई को इन्वेंट्री प्रबंधन, माँग पूर्वानुमान और रीयल-टाइम ट्रैकिंग के लिए डिजिटल उपकरण अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने से पारदर्शिता और दक्षता बढ़ सकती है। सार्वजनिक-निजी भागीदारी को मज़बूत करना और बुनियादी ढाँचे के लिए वित्तीय प्रोत्साहन या सब्सिडी प्रदान करना।

उन्नयन और लॉजिस्टिक्स आधुनिकीकरण स्टार्टअप्स के लिए प्रेरक का काम कर सकते हैं। साझा बुनियादी ढाँचे को सक्षम करने के लिए औद्योगिक समूहों या एमएसएमई पार्कों को बढ़ावा देने से लागत कम करने और संबंधित उद्यमों के बीच समन्वय में सुधार करने में मदद मिल सकती है। एमएसएमई कर्मचारियों को आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में प्रशिक्षित करना और खरीद, उत्पादन और वितरण को अनुकूलित करने के लिए डिजिटल उपकरणों का उपयोग करना कार्य प्रवाह को आसान बना सकता है। एमएसएमई को किफायती परिवहन और वेयरहाउसिंग सेवाओं तक पहुँच प्रदान करने में मदद करने के लिए साझा लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म बनाने से परिवहन सुचारू हो सकता है। सरलीकृत और सुव्यवस्थित नियामक प्रक्रियाएँ सीमा शुल्क निकासी और अंतरराज्यीय परिवहन जैसी आपूर्ति श्रृंखला प्रक्रियाओं में देरी को कम कर सकती हैं। इन मुद्दों को समग्र रूप से संबोधित करके, एमएसएमई उत्पादकता में सुधार कर सकते हैं, परिचालन लागत कम कर सकते हैं और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में बेहतर प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं।

एमएसएमई की वैश्विक व्यापार उपस्थिति को मजबूत करने की रणनीतियाँ

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए वैश्विक बाजार पहुँच का विस्तार करना उनके विकास और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। एक बहुआयामी रणनीति एमएसएमई को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने और नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए सशक्त बना सकती है। कौशल विकास और निर्यातोन्मुखी प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता निर्माण MSMEs को अंतर्राष्ट्रीय मानकों, व्यापार नीतियों, दस्तावेज़ीकरण और गुणवत्ता अनुपालन के बारे में ज्ञान प्रदान करता है। निर्यात संवर्धन परिषदों और व्यापार निकायों के साथ सहयोग जागरूकता और आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद कर सकता है। डिजिटलीकरण MSMEs के लिए एक क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है यदि वे अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों तक पहुँचने, बिचौलियों पर निर्भरता कम करने और लॉजिस्टिक्स का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करने के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का लाभ उठाते हैं। डिजिटल मार्केटिंग और SEO में निवेश करने से वैश्विक बाजारों में उनकी दृश्यता बढ़ती है। सभी व्यावसायिक गतिविधियों के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए। कम ब्याज दर वाले निर्यात ऋण तक पहुँच।

बीमा और वित्तीय साक्षरता एमएसएमई को अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन प्रबंधित करने और जोखिमों को कम करने में मदद करती है। भारत की निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तुएँ (ईपीसीजी) और बाज़ार पहुँच पहल (एमएआई) जैसी सरकारी योजनाएँ निर्यात प्रबंधन के लिए आवश्यक सहायता प्रदान कर सकती हैं। प्रभावी व्यापार लॉजिस्टिक्स और अनुपालन के माध्यम से व्यापार सुविधा में सुधार किया जाना चाहिए। डिजिटल व्यापार प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करके दस्तावेज़ीकरण और सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को सरल बनाना, निर्यात दस्तावेज़ीकरण को कम करना और तेज़ मंजूरी सुनिश्चित करना एमएसएमई को अंतर्राष्ट्रीय समय-सीमा को पूरा करने में मदद करता है। एमएसएमई समूहों में निर्यात व्यापार सुविधा केंद्र स्थापित करने से स्थानीय समर्थन भी मिल सकता है। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और एमएसएमई-अनुकूल प्रावधानों वाले एफटीए का लाभ उठाकर उनकी भागीदारी को बढ़ावा देना चाहिए। साझेदारी और नेटवर्किंग किसी भी व्यवसाय के लिए प्रमुख समर्थन हैं। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों, बी2बी बैठकों और व्यापार मिशनों में भागीदारी एमएसएमई को वैश्विक खरीदारों और भागीदारों से जोड़ सकती है। नवाचार और उत्पाद विविधीकरण को वैश्विक मांग के रुझानों के साथ जोड़ा जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि एमएसएमई की पेशकशें प्रतिस्पर्धी बनी रहें। पैकेजिंग, प्रमाणन और लॉजिस्टिक्स पर मार्गदर्शन प्रदान करने से उत्पादों में दृश्य आकर्षण बढ़ सकता है, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार गुणवत्ता मानक बनाए रखने से विदेशी बाजारों में आसानी से प्रवेश मिल सकता है। डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से भारतीय ब्रांडों को स्थापित करने और उनका प्रचार करने के लिए ई-मार्केटप्लेस और प्रभावशाली मार्केटिंग का उपयोग कई दम तोड़ते उद्योगों के लिए वरदान साबित हो सकता है। इन रणनीतियों को अपनाकर, एमएसएमई प्रवेश बाधाओं को दूर कर सकते हैं, निर्यात को बढ़ावा दे सकते हैं और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

नीति निर्माण में सरकारी हस्तक्षेप की भूमिका

सरकार की लापरवाही एमएसएमई के विकास में गंभीर बाधा डाल सकती है। पर्याप्त नीतिगत समर्थन, वित्त पोषण तक पहुँच, बुनियादी ढाँचे के विकास और नियामक व्यवस्था के बिना सरलीकरण के बावजूद, एमएसएमई को कुशलतापूर्वक संचालन करने में कठिनाई होती है।

सुधारों को लागू करने में देरी, जागरूकता कार्यक्रमों की कमी और अपर्याप्त प्रोत्साहन नवाचार को हतोत्साहित करते हैं, प्रतिस्पर्धात्मकता को कम करते हैं और घरेलू और वैश्विक दोनों बाजारों के अवसरों को सीमित करते हैं। जटिल नियम और अनुपालन का बोझ व्यापार सुगमता में बाधा डालते हैं। इसलिए सरकारी नीति और नियामक सुधारों को एक सहायक और सक्षम व्यावसायिक वातावरण बनाकर एमएसएमई के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तैयार किया जाना चाहिए। प्रक्रियाओं का सरलीकरण व्यवसाय पंजीकरण, लाइसेंसिंग और अनुपालन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने में मदद कर सकता है, नौकरशाही बाधाओं को कम कर सकता है, जिससे एमएसएमई के लिए समय और लागत की बचत होती है। ऋण तक पहुँच को आसान बनाने वाली नीतियाँ—जैसे कि संपार्श्विक-मुक्त ऋण, ब्याज सब्सिडी और ऋण गारंटी योजनाएँ—एमएसएमई को विकास, नवाचार और प्रौद्योगिकी में निवेश करने के लिए सशक्त बनाती हैं। कर बोझ कम करने और लक्षित सब्सिडी एमएसएमई को वित्तीय रूप से व्यवहार्य और प्रतिस्पर्धी बने रहने में मदद कर सकती हैं, जिससे पुनर्निवेश और विस्तार को प्रोत्साहन मिलता है। ऐसे सुधार जो अनुबंधों के प्रवर्तन में सुधार करते हैं, लालफीताशाही को कम करते हैं और विवादों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करते हैं, एमएसएमई के विकास के लिए एक स्थिर और पूर्वानुमानित वातावरण बनाते हैं। औद्योगिक पार्कों, परिवहन और डिजिटल बुनियादी ढांचे में सरकारी निवेश एमएसएमई को सीधे तौर पर लाभान्वित करता है, जिससे परिचालन लागत कम होती है और आपूर्ति श्रृंखला दक्षता में सुधार होता है। डिजिटल परिवर्तन और कार्यबल के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल और कौशल विकास नीतियों को लागू किया जाना चाहिए ताकि एमएसएमई आधुनिक प्रथाओं को अपना सकें और वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धा कर सकें। निर्यात प्रक्रियाओं को सरल बनाने, बाजार की जानकारी प्रदान करने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए निर्यात संवर्धन और व्यापार सुविधा पर केंद्रित सुधारों को व्यवहार में लाया जाना चाहिए। समावेशी और लक्षित कार्यक्रम शुरू किए जाने चाहिए और संतुलित और समावेशी आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं के नेतृत्व वाले, ग्रामीण या क्षेत्र-विशिष्ट एमएसएमई का समर्थन करने के लिए नीतियों को तैयार किया जाना चाहिए।

संक्षेप में, सक्रिय और सुविचारित नीति और नियामक सुधार नवाचार, रोज़गार और आर्थिक लचीलेपन के इंजन के रूप में एमएसएमई की पूरी क्षमता का उपयोग किया जा सकता है। एकल-खिड़की मंजूरी, डिजिटल दस्तावेज़ीकरण और कर सरलीकरण लालफीताशाही को कम कर सकते हैं। लचीले लेकिन निष्पक्ष श्रम कानून, कामगारों के अधिकारों को सुनिश्चित करते हुए, नियुक्ति को प्रोत्साहित कर सकते हैं। 'कौशल भारत' के तहत कार्यक्रमों को उद्योग की ज़रूरतों के साथ, विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी एमएसएमई में, और अधिक निकटता से जोड़ा जाना चाहिए।

सुझाव:

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) आर्थिक विकास, रोज़गार सृजन और नवाचार में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता हैं, विशेष रूप से भारत जैसी विविध अर्थव्यवस्था में। हालाँकि, अपने महत्व के बावजूद, एमएसएमई को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो उनके विकास को सीमित करती हैं और स्थानीय और वैश्विक दोनों बाज़ारों में उनकी भागीदारी को सीमित करती हैं। उनकी स्थिति को मज़बूत करने के लिए, नीतिगत समर्थन, प्रौद्योगिकी अपनाने, कौशल विकास, बुनियादी ढाँचे में सुधार और बाज़ार पहुँच को सुगम बनाने वाली एक व्यापक रणनीति आवश्यक है। बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करना एमएसएमई के लिए एक मौलिक आवश्यकता है। कई एमएसएमई खराब कनेक्टिविटी, अविश्वसनीय बिजली आपूर्ति और अपर्याप्त डिजिटल बुनियादी ढाँचे वाले क्षेत्रों में काम करते हैं। औद्योगिक समूहों, परिवहन नेटवर्क और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी में सरकारी निवेश परिचालन अक्षमताओं को काफी हद तक कम कर सकता है और एमएसएमई को अपने परिचालन को अधिक कुशलता से बढ़ाने में मदद कर सकता है। नीति और नियामक सुधारों को अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाने, लालफीताशाही को कम करने और व्यापार में आसानी सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उद्यम पंजीकरण, आपातकालीन ऋण गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) और एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) जैसी योजनाओं का समय पर कार्यान्वयन लक्षित सहायता प्रदान कर सकता है। स्पष्ट निर्यात नीतियां, प्रोत्साहन और कम दस्तावेज़ीकरण एमएसएमई को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। वित्त तक पहुँच एक महत्वपूर्ण बाधा बनी हुई है क्योंकि एमएसएमई अक्सर औपचारिक बैंकिंग संस्थानों द्वारा आवश्यक संपार्श्विक या क्रेडिट इतिहास का अभाव है।

सूक्ष्म वित्त संस्थानों की पहुँच का विस्तार, संपार्श्विक-मुक्त ऋण प्रदान करना और ऋण गारंटी तंत्र को मजबूत करना ऋण अंतर को पाट सकता है। उद्यमियों को बेहतर निर्णय लेने के कौशल से सशक्त बनाने के लिए वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के उद्देश्य से एमएसएमई का डिजिटल परिवर्तन ई-कॉमर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल मार्केटिंग को अपनाने को प्रोत्साहित कर सकता है जिससे उन्हें अपने ग्राहक आधार का विस्तार करने और आपूर्ति श्रृंखला दक्षता में सुधार करने में मदद मिल सकती है। सरकार द्वारा संचालित डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम, तकनीक अपनाने के लिए सब्सिडी और तकनीकी कंपनियों के साथ साझेदारी इस परिवर्तन को सुगम बना सकती है। कौशल विकास और नवाचार समान रूप से आवश्यक हैं, इसलिए एमएसएमई को अपने कार्यबल को कुशल बनाने और अनुसंधान एवं विकास को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। शैक्षणिक संस्थानों के साथ संबंध बनाना, नवाचार केंद्र स्थापित करना और स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करना रचनात्मकता और निरंतर सुधार की संस्कृति को बढ़ावा दे सकता है। बाज़ार पहुँच में वृद्धि भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, इसलिए स्थानीय स्तर पर, एमएसएमई को सार्वजनिक खरीद प्रणालियों में एकीकृत किया जाना चाहिए और आपूर्तिकर्ता विकास कार्यक्रमों के माध्यम से बड़ी कॉर्पोरेट मूल्य श्रृंखलाओं से जोड़ा जाना चाहिए। वैश्विक स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी, बाज़ार की जानकारी तक पहुँच और ब्रांडिंग एवं पैकेजिंग में सुधार के लिए समर्थन, एमएसएमई उत्पादों को प्रतिस्पर्धी रूप से स्थापित करने में मदद कर सकते हैं। निर्यात सुविधा केंद्र स्थापित करना और एमएसएमई को व्यापार विशेषज्ञों से जोड़ना उनकी निर्यात तैयारी को बढ़ा सकता है। स्थिरता और गुणवत्ता आश्वासन भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये पर्यावरण-अनुकूल प्रथाओं को प्रोत्साहित करते हैं, गुणवत्ता जांच प्रमाणपत्र प्रदान करते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ गुणवत्ता अनुपालन सुनिश्चित करते हैं जिससे वैश्विक बाज़ारों में उनकी विश्वसनीयता और स्वीकृति में सुधार होता है।

निष्कर्ष

भारत के एमएसएमई में वैश्विक अग्रणी बनने की क्षमता है। डिजिटल सशक्तिकरण, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और नीतिगत सुधारों के माध्यम से रणनीतिक समर्थन आवश्यक है। भारतीय एमएसएमई का भविष्य घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में प्रतिस्पर्धी खिलाड़ी बनने में निहित है। भारत का एमएसएमई क्षेत्र समावेशी विकास, नवाचार और रोजगार को बढ़ावा देने की अपार क्षमता रखता है। संरचनात्मक बाधाओं को दूर करके, प्रौद्योगिकी और वित्त तक पहुँच में सुधार करके और मजबूत बाजार संबंध बनाकर, सरकार, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज मिलकर एमएसएमई के लिए एक समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर सकते हैं। आज एक सक्रिय दृष्टिकोण भारतीय एमएसएमई को भविष्य के वैश्विक चैंपियन में बदल सकता है। निष्कर्षतः, स्थानीय और वैश्विक दोनों बाजारों में एमएसएमई की वर्तमान स्थिति को बेहतर बनाने के लिए सरकार, औद्योगिक निकायों, वित्तीय संस्थानों और उद्यमियों के समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है। मुख्य चुनौतियों का समाधान करके और उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाकर, एमएसएमई समावेशी और सतत आर्थिक विकास के शक्तिशाली इंजन में तब्दील हो सकते हैं, जो भारत के 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।

संदर्भ

•सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय। (2023)। वार्षिक रिपोर्ट 2022-23।

भारत सरकार।

•भारतीय रिज़र्व बैंक। (2023)। भारत में बैंकिंग के रुझान और प्रगति पर रिपोर्ट।

विश्व बैंक। (2022)। भारत: एमएसएमई प्रदर्शन को बढ़ाना और तेज़ करना (आरएएमपी) परियोजना।

• फिक्की। (2022)। एमएसएमई प्रतिस्पर्धात्मकता और बाज़ार पहुँच: चुनौतियाँ और आगे की राह।

- भारतीय उद्योग परिसंघ। (2021)। भारतीय एमएसएमई क्षेत्र की पुनर्कल्पना।
- कुमार, एस. और सिंह, आर. (2020)। एमएसएमई के लिए डिजिटल परिवर्तन और बाज़ार पहुँच। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बिज़नेस रिसर्च, 15(3), 45–56।

• चित्र 1 पीआईबी/एमएसएमई मंत्रालय: सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 30% हिस्सेदारी, लगभग 45-48% निर्यात, और उद्यम पंजीकरणों के माध्यम से रोज़गार के आँकड़े (~203.9 मिलियन) की पुष्टि करता है।

pib.gov.in+1en.wikipedia.org+1

शैक्षणिक अनुसंधान और उद्योग ब्लॉग: 2024-25 में भी यही आँकड़े दर्शाते हैं।

pib.gov.in+1timesofindia.indiatimes.com+1

• चित्र 2 स्रोत: सिडबी की रिपोर्ट "भारतीय एमएसएमई क्षेत्र को समझना: प्रगति और चुनौतियाँ", मई 2025 linkedin.com+11sidbi.in+11iabgroup.org.uk+11।

आँकड़े: 19 क्षेत्रों में 2,097 एमएसएमई के राष्ट्रीय सर्वेक्षण पर आधारित।